



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राक्षिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 174] तहीं दिल्ली, बृहस्पतिवार, प्रातःकाल, 15, 1970/ग्रादिन 23, 1892

No. 174] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 15, 1970/ASVINA 23, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संलग्न वी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF PETROLEUM & CHEMICALS AND MINES & METALS

(Department of Mines and Metals)

RESOLUTION

New Delhi, the 12th October 1970

No. CI-13 (II)/70.—The Government of India have been considering for some time past the question of formulating a long term Fuel Policy. The Energy Survey Committee, in their 1965 Report, found that our energy resources are adequate, but not abundant. They recommended that it was desirable to keep under review the trends in energy consumption as circumstances change. The energy consumption pattern indicates a growing dependence on liquid fuels although indigenous coal resources are available in abundance. It is considered necessary to evaluate all the available fuel resources in the country with a view to optimise utilisation of the same. Hence the Government have decided to set up a high level Fuel Policy Committee. The Committee will consist of the following:—

Chairman.

1. Shri R. Venkataraman, Member (Industry), Planning Commission.
Members.
2. Shri M. Dutta Chowdhury, Professor of Transport Economics, Delhi School of Economics, Delhi.
3. Vice Chairman, Central Water & Power Commission, New Delhi.

4. Dr. M. G. Krishna, Director, Indian Institute of Petroleum, Dehradun.
5. Dr. A. Lahiri, Director, Central Fuel Research Institute, Dhanbad.
6. Shri R. Lal, Managing Director, Bengal Coal Company Ltd., Calcutta.
7. Shri B. S. Negi, Member (Exploration), Oil and Natural Gas Commission, Dehradun.
8. Dr. Kirit Parikh, Director, Programme Analysis Group, Atomic Energy Commission, Bombay.
9. Dr. B. Ramamurti, (Statistician, lately of ECAFE).
10. Shri K. Vaidyanathan, Additional Member (Mechanical), Railway Board, New Delhi.
11. Shri Rasiklal Wohra, President, Indian Colliery Owners Association, Dhanbad.

Shri T. L. Sankar, Deputy Secretary, Department of Mines and Metals, will act as the full time Secretary of the Committee.

2. The terms of reference of the Committee will be as follows:—
 - (a) Undertake a survey of fuel resources and the regional pattern of their distribution;
 - (b) Study the current trends in exploitation and use of fuels;
 - (c) Estimate prospective demand by sectors (in particular the transport industry, power generation industry and domestic fuel) and by regions;
 - (d) Study the efficiency in the use of fuel, and recommend—
 - (i) the outline of a national fuel policy for the next fifteen years;
 - (ii) a pattern of consumption and measures, fiscal and otherwise, which would help the best use of available resources; and
 - (iii) the measures and agencies, to promote the optimum efficient use of fuel.

3. The Committee will submit its report to the Government of India, Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Department of Mines and Metals), New Delhi, within a period of one year.

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India Extraordinary for general information.

N. SUBRAHMANYAM, Secy.

पेट्रोलियम तथा रसायन और लान तथा धातु संग्रासम्

(लान तथा धातु विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर, 1970

संख्या क्र० १-१३(११) / ७०.—भारत सरकार विभाग ममता से दीघीविधि ईंधन नीति बनाने के प्रस्तुत पर विचार करती आ रही है। ऊर्जा सर्वेक्षण समिति ने अपनी १९६५ की रिपोर्ट में यह पाया कि ऊर्जा संसाधन पर्याप्त है परन्तु प्रचुर नहीं है। उन्होंने यह सिफारिश की कि जैसे परिस्थितियाँ परिवर्तित होती रहे वैसे ही ऊर्जा उपभोग में प्रवृत्ति को पुनरीक्षणीय रखना बांधनीय है ऊर्जा उपभोग पर्टन तरल ईंधनों पर वर्धित निर्भरता उपदण्डित करता है यथापि स्वदेशी कोयला संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। ईंधन संसाधनों का उपयोजन को आणाजनक रखने की वृत्ति से देश में समस्त उपलब्ध ईंधन संसाधनों

का निर्धारण करना आवश्यक भाना गया है। अतः सरकार ने यह विनिश्चय किया है कि एक उच्च स्तरीय ईंधन-नीति-समिति स्थापित की जाए, जिसमें नियन्त्रित विनियोग पदाधिकारी होंगे :—

अध्यक्ष

1. श्री आर० बेन्कटारमन, सदस्य (उद्योग) गोंजना आयोग।

सदस्य

2. श्री एम० दत्त चौधरी, प्रो० परिवहन आयिक, दिल्ली स्कूल आफ इन्डियन, दिल्ली।

3. उपाध्यक्ष, केन्द्रीय जल एवं शक्ति आयोग, नई दिल्ली।

4. डॉ एम० जी० छृष्ण, निदेशक, टाइपिंग इन्स्ट्रीट्री आफ पेट्रोलियम, देहरादून।

5. डॉ ए० लहोरी, निदेशक, केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान सम्बान्ध, घनदेह।

6. श्री आर० लाल, प्रबन्ध निदेशक, बगाल कोल कम्पनी लिमिटेड, जगकला।

7. श्री बी० एम० नेरा० मदन्य (ममन्त्रियण) तेल एवं नैसर्गिक गैस आयोग, देहरादून।

8. डॉ ओर्सित पारिख, निदेशक, प्रोप्रेस अनालिसिस ग्रुप, एकॉमिक ऊर्जा आयोग, बम्बई।

9. डॉ बी० रामामूर्ति, (मास्यकी भूतपूर्व इसी प्रकार ई)

10. श्री कौ० वैद्यनाथन, प्रतिरिक्ष मदस्य (यांत्रिक) रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली।

11. श्री रसिक लाल बोहरा, अध्यक्ष, इण्डियन कोलरी औनस एक्सिमायन, घनदेह।

श्री टी० एल० गंकर, उप-मचिव, खान तथा धातु विभाग, समिति के पूर्ण कार्यक मचिव के स्वरूप में कार्य करेंगे।

2. समिति के निर्देशन-निबन्धन निम्न प्रकार में होंगे :—

(क) ईंधन संसाधनों के मंबोक्षण का कार्य करेगी एवं उनके वितरण का धोर्त्वाद रेहम तंत्रज्ञान करेगी;

(ख) समुपयोजन एवं ईंधनों के उपयोग में चान्त्र प्रवृत्ति का अध्ययन;

(ग) स्वक्षरा द्वारा तथा धोर्त्वा द्वारा पुर्वोक्षण मोर्ग वा प्रावक्षलन (विस्तृप्त परिवर्तन उद्योग, शक्ति जनक उद्योग और धरोल् ईंप्रेस)

(घ) ईंधन के उपयोग में दक्षता—अध्ययन आरो

(1) आयामी पन्द्रह वर्षों के लिए राष्ट्रीय ईंधन मीलिं की रूप रेखा;

(2) उपभोग तथा उपायों, वित्तीय और अन्यथा का पैटर्न, जो उपलब्ध संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग में सहायता करेगा;

(3) इधन के प्रभायनकर्ता पूर्ण उपयोग को बढ़ाने के लिए उपाय एवं अभिकरण के लिए विकारिण देंगे।

3. ममिनि एक वर्ष की कानाकाधि के अन्दर भारत सरकार, पेट्रोलियम तथा रसायन और खाना तथा धानु (खान तथा धानु विभाग) मंत्रालय को अपनी लिपोर्ट देंगी।

अ. यह दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी सम्पूर्णों को संसूचित किया जाए।

यह भी प्रादेश दिया जाता है कि यह संकल्प वर्व माधारण की सूचना के लिए भारत के राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए।

एन० सुन्दरप्पम्, सचिव।